भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1489

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2021

दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल टावर

1489. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार डिजिटलकरण की मांग को पूरा करने और ग्रामीण बैंकिग प्रणाली को मजबूत करने के लिए देश की प्रत्येक पंचायत में मोबाइल टावर लगाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के दूर-दराज के उन गांवों में मोबाइल टावर उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं जहां अभी तक ये टावर उपलब्ध नहीं हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के प्रत्येक दूर-दराज के गांवों और प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (घ) दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी) ने वर्ष 2020 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि देश के 5,97,618 आबादी वाले मतगणना किए गए गांवों में से लगभग 5,72,551 गांवों में पहले से ही मोबाइल कवरेज उपलब्ध है। बसे हुए 25,067 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है। सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी) के माध्यम से देश के सेवा से वंचित गांवों में चरणबद्ध रूप से मोबाइल कवरेज प्रदान कर रही है। सरकार ने पहले चरण में पूर्वोत्तर राज्यों, द्वीपसमूह, हिमालयी राज्यों, पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों और वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्लू.ई) से प्रभावित क्षेत्रों जैसे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवा की पहुंच को प्राथमिकता दी है। इस संबंध में सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ) को अनुमोदित किया है जिसके द्वारा देश भर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने/सुविधा प्रदान करने हेतु स्कीमों/परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। ये स्कीमें निम्नानुसार हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद चरण-I परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित 2355 टावर स्थलों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

(ii) एल.डब्ल्यू.ई चरण-।। परियोजना के तहत इन राज्यों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 2542 मोबाइल टावर संस्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। दिनांक 11.03.2021 को 2542 टावरों के लिए निवेदन प्रस्ताव (आर.एफ.पी) जारी किया गया है।

(iii) जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित सेवा से वंचित सीमावर्ती क्षेत्रों के 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भी अनुमोदन दिया गया है और दिनांक 28.04.2020 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस स्कीम को अक्टूबर, 2021 तक शुरू किया जाना है।

(iv) दिनांक 20.12.2019 को चार राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा प्रदान करने हेतु "आकांक्षी जिला स्कीम" को दिनांक 20.12.2019 को अनुमोदित कर दिया गया है और कार्य आवंटित कर दिया गया है।

(v) मेघालय और अरूणाचल प्रदेश एवं असम के दो जिला (कार्बी आंगलोंग एवं दीमा हसाओ) में 4जी मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था के लिए यू.एस.ओ.एफ द्वारा वित्तपोषित की गई दो स्कीमों को निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है:

(क) मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ और सेवा वंचित 1164 गांवों में 889 मोबाइल टावरों का संस्थापन। दिनांक 04.09.2020 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से 21 माह तक की है।

(ख) अरूणाचल प्रदेश के सेवा से वंचित 1683 गांवों में 980 और असम के दो जिलों (कार्बी आंगलोंग एवं दीमा हसाओ) के सेवा से वंचित 691 गांवों में 531 मोबाइल टावरों का संस्थापन। कार्यान्वयन एजेंसी के चयन के लिए दिनांक 04.03.2021 को आर.एफ.पी जारी की गई है। मूल्यांकन करने के बाद कार्य आवंटन हेतु निविदा सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा कार्य आवंटन से 18 माह की है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी) ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी हेतु अवसंरचना के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। इन पहलों में स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग/साझाकरण/उदारीकरण, निष्क्रिय एवं सक्रिय अवसंरचना का साझाकरण, मार्गाधिकार नियमावली, 2016 को अधिसूचित करना और मोबाइल टावरों के संस्थापन के लिए सरकारी भूमि/भवनों का उपयोग आदि शामिल हैं। इन पहलों के फलस्वरूप देश भर में मार्च, 2014 (6.49 लाख बी.टी.एस) से 21 जुलाई, 2021 (22.54 लाख बी.टी.एस) की अवधि के दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी.एस.पी) द्वारा 2जी/3जी/4जी- एल.टी.ई सेवाओं के लिए लगभग 16.05 लाख अतिरिक्त बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस) जोड़े गए हैं।

*****